

निराकरण से पहले ही सीएम हेल्प लाइन की शिकायत बंद करने की धमकी

देवसर तहसीलदार बीके पटेल के उपर पीड़ित ने लगाया आरोप

आरआई के उपर इश्वत लेने का भी लगाया आरोप
सीमांकन एवं नक्शा तरमीम के लिए दो साल से भटक रहे पीड़ित को नहीं मिल रहा व्याय
एसडीएम देवसर से हुई शिकायत



सिंगरौली

लेकिन सीमा चिन्हित नहीं किए, जिससे असंतुष्ट होकर पीड़ित ने सीएम हेल्प लाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार तहसीलदार ने 12 जून को तहसील कार्यालय में पीड़ित से यह कहा कि तुम सीएम हेल्प लाइन की शिकायत बंद कर दो। अब एक हफ्ते में मैं स्वयं स्थल पर चलकर सीमांकन करवाता हूं। अब एक हफ्ते से ज्यादा समय गुजर गया और अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ।

मामले पर एक नजर

पीड़ित ने बताया कि ग्राम खोमा की आरजी नं. 181/1/13/1 रक्वा 0.070 हे. के नक्शा तर्मीम एवं सीमांकन बाबत विविध आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके सम्बन्ध में तहसील कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर राजस्व निरीक्षक गिर्द बलजीत रावत को पत्र क्रमांक 284/2024 आदेश दिनांक 11/03/2024 जारी किया गया है। एक सप्ताह के अनुर कार्यालय देवसर में दिया है। आवेदन पर संबंधित पटवारी एवं आरआई पिछले दिनों सीमांकन करने गए थे।

तहसीलदार तहसील देवसर के समक्ष प्रस्तुत किया जावे लेकिन कार्यवाही न होने की पुनः मरण पत्र क्रमांक 600/2024 दिनांक 17/05/2024 को जारी किया गया कि राजस्व निरीक्षक एक सप्ताह के अन्दर नक्शा तर्मीम व सीमांकन कर पालन प्रतिवेदन भेजा जावे किन्तु राजस्व नि�रीक्षक द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

राजस्व निरीक्षक के उपर रिश्वत लेने का आरोप

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा 5000 रुपये ले लिया गया है और 15000 रुपये और मांग की है।

बताया गया कि रिश्वत लेने के बाद भी निराकरण नहीं किया गया।

निराकरण से पूर्व ही बंद करवा दिए शिकायत

आरोप यह भी लगाया गया है कि जब निराकरण नहीं हो सका तब आवेदक द्वारा सीएम हेल्प लाइन पर अपनी शिकायत दर्ज कराई गया है। एक सप्ताह के अनुर कार्यालय देवसर में प्रतिवेदन

जाने पर तहसीलदार द्वारा कुछ स्थानीय जनों के समक्ष 12 जून को शिकायत कटवाये जाने हेतु मोबाइल नं. मांग कर समाप्त करवाया गया और कहा गया कि एक सप्ताह के अन्दर सीमांकन हो जाएगा। किन्तु आज 2 सप्ताह गुजर गया और अभी तक तहसीलदार देवसर द्वारा कोई सीएम हेल्प लाइन की गई।

पीड़ित ने कहा कि कार्यवाही नहीं की गई।

रिश्वत लेने का आरोप

पीड़ित ने आरोप लगाया है कि संबंधित राजस्व निरीक्षक द्वारा 5000 रुपये ले लिया गया है और 15000 रुपये और मांग की है। जिसकी तहकीकात सीमांकन के फुटेज से देखा जा सकता है।

दो साल से भटक रहे पीड़ित को नहीं मिल रहा व्याय

पीड़ित सीमांकन व नक्शा तर्मीम न होने से काफी परेशान हो रहा है। चूंकि उसके द्वारा मकान निर्माण होते में मूल्य रूप से उपनिरीक्षक भी पैदेंद पाठक, सर्वज्ञ छत्रपाल पांडे, राजकुमार त्रिपाठी, प्राआर नंदें यादव, उमाशंकर सिंह, थाना बरगांव के आरक्षक विकेश सिंह एवं जिला सीधी में उपनिरीक्षक मोनिका पांडे, प्रधान आरक्षक रविंद्र सिंह ने संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया।

घर से गायब नाबालिका को पुलिस ने सीधी से किया दस्तयाब

सिंगरौली

पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता द्वारा गुम इंसान को दस्तयाब करने के दिशा निर्देश मिलने के बाद से ही जिले भर की पुलिस थाना क्षेत्र से गायब लोगों को तलाश करने में जुटी है। इसी परिषेक में गोरबी पुलिस ने भी चौकी क्षेत्र के महदेश्य से लापता एक नाबालिका को कड़ी मशक्त के बाद सीधी से दस्तयाब कर परिजनों को सौंप दिया। अपनी बच्ची को सही सलामत पाकर परिजन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह पुलिस की सराहना करते दिखे। ममला मोरवा थाना क्षेत्र के गोरबी चौकी अंतर्तात ग्राम महदेश्य किया गया।



किसी अनहोनी घटना से सम्पर्क साधक कर तत्काल 24 घंटे के भीतर बालिका को सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया। इस संपूर्ण कार्यवाही में मुख्य रूप से उपनिरीक्षक भी पैदेंद पाठक, सर्वज्ञ छत्रपाल पांडे, राजकुमार त्रिपाठी, प्राआर नंदें यादव, उमाशंकर सिंह, थाना बरगांव के आरक्षक विकेश सिंह एवं जिला सीधी में उपनिरीक्षक मोनिका पांडे, प्रधान आरक्षक रविंद्र सिंह ने संवेदनशीलता एवं तत्परता के साथ अपनी भूमिका का निर्वहन किया।

एएसपी ने किया पुलिस लाईन का वार्षिक निरीक्षण



अधिकारी कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। स्टार शाखा का निरीक्षण कर शासकीय संपत्ति को ठोक से रखरखाव के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। वाहन शाखा का निरीक्षण कर वाहनों से संबंधित अधिलोकन किया। पुलिस लाइन और थानों के समस्त वाहनों का अधीक्षक गोर्ड एवं पालामी लेकर गार्ड का निरीक्षण किया। पुलिस लाइन की वार्षिक शाखा, कैश शाखा, कैश नामांचा शाखा, वाहन शाखा, स्ट्रीट्रायर, रार्ड एवं एसडीओपी का अधीक्षक गोर्ड एवं पालामी लेकर गार्ड का निरीक्षण किया। अधिकारी एवं एसडीओपी का अधीक्षक गोर्ड एवं पालामी लेकर गार्ड का निरीक्षण किया।

वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य रूप से लगवाए : आरपी मिश्रा

यातायात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा जागरूकता अभियान



सिंगरौली। पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता के निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवकुमार वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक पीएस परस्ते के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस टीम के द्वारा शहर के चौराहो एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यातायात नियमों की जागरूकता के तहत हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लाइन वर्तमान वाहनों से संबंधित अधिकारी एवं एसडीओपी के द्वारा यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं।

वितरित किये गये। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और परिवहन विभाग ने 1 अप्रैल 2019 से पहले बेचे गए वाहनों पर कलर कोडें प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार सभी वाहन मालिकों को 30 जून 2024 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य है। वाहनों यातायात नाम प्रधारी आरपी एसआर अधिकारी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इस अवधि पर नगर निगम के अधिकारी राजीव सिंह, पार्षद शेखर सिंह, आरपी गुप्ता अधिकारी एवं संबंधित वाहनों को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इस अवधि पर नगर निगम के अधिकारी राजीव सिंह, पार्षद शेखर सिंह, आरपी गुप्ता अधिकारी एवं संबंधित वाहनों को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया।

प्रधारी आरपी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इस अवधि पर नगर निगम के अधिकारी राजीव सिंह, पार्षद शेखर सिंह, आरपी गुप्ता अधिकारी एवं संबंधित वाहनों को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। इस अवधि पर नगर निगम के अधिकारी राजीव सिंह, पार्षद शेखर सिंह, आरपी गुप्ता अधिकारी एवं संबंधित वाहनों को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया।

प्रधारी आरपी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया।

प्रधारी आरपी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया।

प्रधारी आरपी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया।

प्रधारी आरपी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया।

प्रधारी आरपी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया।

प्रधारी आरपी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागरूक करने के लिए उन्हें प्रेरित किया गया।

प्रधारी आरपी एवं एसडीओपी को रोकथाम एवं यातायात नियमों के प्रति आम जनता को जागर

प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस बना संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय सीधी

सीधी। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन ने उच्च शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार, दक्षता में बढ़िए लाने तथा छात्र-छात्राओं को सरलता से रोजगार उपलब्ध हो इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशनुसार प्रदेश के 55 महाविद्यालयों को प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया है। प्रत्येक जिले के एक-एक महाविद्यालय को इसके लिए चुना गया है। सीधी जिले से यह उपलब्ध संजय गांधी स्मृति शासकीय महाविद्यालय को मिली है, जिसके उद्घाटन दीक्षारंभ कार्यक्रम की तैयारी चल रही है।

महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ पी के सिंह ने जानकारी देकर बताया कि महाविद्यालय में कुछ नवीन पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे जिनमें बायोटेक, मोनोविज्ञान एवं कंप्यूटर साइंस इसी सत्र से स्नातक कक्षाओं में प्रारंभ हो रहा है, जबकि संस्कृत में स्नातकोत्तर की कक्षाएं इव वर्ष से संचालित होंगी, जिनके एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही

खुलेंगे नए पाठ्यक्रम, 1 जुलाई को होगा दीक्षारंभ कार्यक्रम



Samsung Triple Camera Shot with my Galaxy A50s

बीकाम में नया पाठ्यक्रम रिटेल और ऐरेशन मैनेजमेंट भी प्रारंभ हो चुका है। बी.एड.एवं कृषि में स्नातक भी प्रारंभ करना है जिसकी शुरुआत करने की प्रारंभिक कार्यवाही चल रही है जो जल्द ही खुलेगा जिससे विद्यार्थियों को प्रवेश के लिए पोर्टल पर प्रदर्शित होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं किनेटिक कॉर्सेज से संबंधित डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए जाएंगे। छात्र-छात्राओं की आवागान की सुविधा के लिए 1 जुलाई से बस सेवा प्रारंभ की

जावेगी जिसका प्रति दिवस का रूट निर्धारित होगा। उहाँने बताया कि महाविद्यालय में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी का आउटलेट भी खुलेगा जिससे विद्यार्थियों को समय पर सभी गतिविधियों की जानकारी हो सके एवं छात्र-छात्राएं उसमें अपनी शुरुआत करने के लिए पुस्तक उपलब्ध होंगी। साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित उसकों की प्रदर्शनी भी लगेगी और समय-समय पर संगोष्ठी का भी आवागान की तैयारी की जाएगी। स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन

योजना अंतर्गत डिप्लोमे के माध्यम से प्रत्येक महीने की गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा जिससे विद्यार्थियों को समय पर सभी गतिविधियों की जानकारी हो सके एवं छात्र-छात्राएं उसमें अपनी शुरुआत कर सकें। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कॉरिज आफ एक्सीलेंस मुख्यमंत्री जी का द्वीप प्रोजेक्ट है जो मध्य प्रदेश को उच्च शिक्षा में शीर्ष पर ले जाएगा तथा जिसका लाभ छात्र-छात्राओं को मिलेगा।

प्राचार्य डॉ सिंह ने सभी नव प्रवेश छात्र-छात्राओं से आग्रह किया है कि 1 जुलाई की दीक्षारंभ कार्यक्रम में सभी आवश्यक रूप से महाविद्यालय में उपस्थित हों जो विद्या वन की निर्माण किया जाना है जो सभी कार्य पीड़ित्यूनी के माध्यम से किये जा रहे हैं। 1 जुलाई के पूर्व सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे।

प्राचार्य डॉ सिंह ने सभी नव प्रवेश छात्र-छात्राओं से आग्रह किया है कि 1 जुलाई की दीक्षारंभ कार्यक्रम में सभी आवश्यक रूप से महाविद्यालय में उपस्थित हों जो विद्या वन की निर्माण समय पर प्राप्त की जा सकती है। प्राप्त निवादा दिनांक 18.07.2024 को अपराह्न 04 बजे कार्यालय कलेक्टर सीधी के सभाकाश में उपस्थित निवादा दाताओं के समक्ष खोली जाएंगी।

विज्ञान एवं शर्त ब आवेदन पत्र का प्रारूप इत्यादि का विवरण जिले के बेवसाइट पर एवं कार्यालय कलेक्टर नजारत शाखा से कार्यालयीन समय पर प्राप्त की जा सकती है।

महिला केन्द्रित विषयों पर 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान

सीधी। भारत सरकार मंत्रालय परिषद सीधी/नगर पंचायत परिषद चुरहट, रम्यमूर नैकिन एवं मझौली को निर्देशित किया है कि उक्त अभियान में परियोजना अधिकारी वाल विभाग विषयों पर 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करें। गतिविधियों की सांसाधिक रिपोर्ट्स फोटोग्राफ्स सहित ईमेल बूकेपक/दफ्तरपत्र पर प्रेषित करें। जिसे संकल्प हब फॉर एम्पायरमेंट ऑफ वूमेन डैशबोर्ड पर अपलोड कराया जा सके। उन्होंने निर्देशित किया है कि संकल्प हब फॉर एम्पायरमेंट ऑफ वूमेन अंतर्गत महिला केन्द्रित विषयों पर 100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान समय बढ़ एवं प्रभावी तरीके से आयोजित कराने में आवश्यक सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करें।

रोजगार मेले में 51 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

सीधी। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देकर बताया है कि दिनांक 26.06.2024 को जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय सीधी द्वारा एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन शासकीय आई.टी.आई. सीधी में किया गया जिसमें ऑफलाइन 104 एवं ऑफलाइन 41 कुल 145 युवक एवं युवतियों ने अपना पंजीयन कराया जिसमें से 51 आवेदकों का प्राथमिक चयन किया गया। उहाँने बताया कि इन्हें विशेष जागरूकता अभियान के द्वारा आयोजित होने वाले एक्सीलेंस कार्यालयीन में 13, एस.आई.एस. सिक्युरिटी सर्विसेज रिपोर्टी में 07 एवं नियन्त्र प्रालिंग और युवतियों का चयन किया गया।

सीधी में जमोड़ी के अमरवाह में करंट लगने से खेत में काम कर रहे पिता-पुत्र की मौत

सीधी। करंट लगने से पिता-पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना सोमवार सुबह सीधी जिले के जमोड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत अमरवाह गांव की है। पीएम के बाद शब्द स्वजन को सौंप दिया है कि अपने के समय पिता-पुत्र दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा दुआ है।

गिरेंद्र प्रसाद द्विवेदी पुत्र सुरेश द्विवेदी 40 वर्षीय विवासी अमरवाह घर में बने बांडेलीबाल के अंदर धन डालने के लिए खेत तैयार कर रहे



थे। उसी दीरान खेत में पहले से बिजली खांध के जीआई तार के चपेट में आ गए। पिता को करंट में फेंटे देख खेत में काम कर रहा थे। उसी दीरान खेत में पहले से बिजली खांध के जीआई तार के चपेट में आ गए। पिता को करंट में फेंटे देख खेत में काम कर रहा थे। जैसे ही ही पिता को बचाने के लिए बाद से गांव में मातम पसरा दुआ है।

म.प्र. पर्यटन क्लिं प्रतियोगिता के लिए पंजीयन 08 जुलाई तक

सीधी। कलेक्टर स्वरोचिष्य सोमवारी के निर्देशन में स्कूल शिक्षा विभाग एवं जिला पुस्तकालय पर्यटन एवं संस्कृति परिवर्त के संयुक्त तत्वधार्म में जिला स्तरीय पर्यटन क्लिं प्रतियोगिता 27 जुलाई को आयोजित होगी। जिसे के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के कक्ष 9 से 12 वीं तक के विद्यार्थियों को प्रदेश के सदरमुकामों इतिहास, पर्यावरण, ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विधायिकाओं, कला, प्राचीनिक समृद्धि, महारूपों, पर्यटन महल की सम्बन्धित आदि से छात्रों को अवगत करने तथा पर्यटन के माध्यम से जागरूक करने के द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्येक विद्यालयीन कॉर्स के लिए जाएगा। शर्मा ने बताया कि करंट लगने से पिता पुत्र की मौत हो गई है। पीएम के बाद से गांव में नाटक और खेत तैयार कर रहे थे।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनीद दुबे ने बताया कि निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने जिले के निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि ये सदन 1975 में देश में आपातकाल (इमरजेंसी) लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके देश से विद्यार्थियों के लिए विद्यालयीन कॉर्स के लिए जाएगा।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनीद दुबे ने बताया कि निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने जिले के निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया की अंतर्गत अवधारणा के लिए जाएगा।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनीद दुबे ने बताया कि निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने जिले के निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया की अंतर्गत अवधारणा के लिए जाएगा।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनीद दुबे ने बताया कि निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने जिले के निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया की अंतर्गत अवधारणा के लिए जाएगा।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनीद दुबे ने बताया कि निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने जिले के निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया की अंतर्गत अवधारणा के लिए जाएगा।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनीद दुबे ने बताया कि निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने जिले के निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया की अंतर्गत अवधारणा के लिए जाएगा।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनीद दुबे ने बताया कि निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने जिले के निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने अपनी त्वरित प्रतिक्रिया की अंतर्गत अवधारणा के लिए जाएगा।

भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुनीद दुबे ने बताया कि निर्वाचित संसद डॉ राजेश मिश्र ने ज

संपादकीय

18वीं लोकसभा- बड़ी हैं चुनौतियां

सोमवार को 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत हो गई। हालांकि शुरुआती दो दिन सांसदों के शपथ ग्रहण की औपचारिकता ही होनी है, लेकिन फिर भी दोनों पार्टी के तेवर पहले ही दिन से यह संकेत दे रहे हैं कि न तो विपक्ष इस बार सदन में अपनी ताकत दिखाना का कोई मौका चूकना चाहता है और न तो सत्ता पक्ष के शपथ ग्रहण के लिए के मूड में है। वैसे संक्षेप बल्कि मैं जो भी थोड़ी-बहुत कमी रह गई हो, तथ्य यह है कि 17वीं लोकसभा में भी विपक्ष ने विरोध की डिग्गी में कोई कमी नहीं रहने दी थी। यह बात सदन के अंदर और बाहर विपक्ष का होगा, बॉकअटर, धरना-प्रदर्शन होंगे, सदन से विपक्ष सांसदों के निलंबन जैसी कार्रवाईयों में भी झलकती रही। बेशक इन सब पर पक्ष और विपक्ष का अपना अलग रुख है, उसके पांछे उनकी अपनी दलीलें भी हैं, लेकिन एक स्तर पर देखा जाए तो यह एक धूमधारी, जिंदा लोकतंत्र की विधानी भी माना जाएगा। विपक्ष की कमज़ोरी-वाचवजूद इसके, पिछली लोकसभा में कई मामलों में सत्ता पक्ष के सामने विपक्ष की कमज़ोरी भी दज होती रही। पिछले करीब दस साल सदन में नेता प्रतिवक्ष की जगह खाली रही। 18वीं लोकसभा में तो कोई डेव्यूटी स्पीकर भी नहीं बनाया गया और विपक्ष सकार को इसके लिए जिम्मेदार नहीं कर सका। विपक्ष का मनोबल हुआ है। इस पृष्ठभूमि में 18वीं लोकसभा में विपक्ष सदस्यों की बड़ी हुंस संख्या उनके मनोबल और आवश्यकास को बढ़ाया हुआ है। पहले दिन ही सदन के बाहर विपक्ष ने यह संकेत दिया कि वे सरकार पर दबाव बनाने का कोई मौका इस बार नहीं चुकना चाहते। दूसरी ओर सत्ता पक्ष भी अपने गठबन्धन की मजबूती को कम समझने वालों के सारे भ्रम दूर करते चलने को कृत संकल्प दिख रहा है।

मौलिक अधिकारों के निलंबन को पर्यवेक्षकों और संविधानिक विशेषज्ञों द्वारा चिंता के साथ याद किया जाता है।

दरअसल आपातकाल की बुनियाद 1967 के गोलकनाथ मामले से ही पड़ गई थी। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि विविधताएँ जैसे बुनियादी मूदों को प्रभावित करते हैं तो संसद द्वारा संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद इस निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए, सरकार ने 1971 में 24वीं संविधान पारित किया। सर्वोच्च न्यायालय में सरकार द्वारा तत्कालीन राजकुमारों को दिए गए प्रतिवेदन के मामले में भी इंदिरा गांधी की किरणिकी हुई थी।

न्यायपालिका-कार्यपालिका की यह लड़ाई ऐतिहासिक क्षेत्रानन्द भारती मामले में जारी रही, जहां 24वीं संविधान पर सबल उत्तरा गया था।

संविधान पर सबल उत्तरा गया था। 7-6 के मामूली बहुमत के साथ, सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने संसद की संशोधन शक्ति को यह कहते हुए प्रतिवर्तीधर कर दिया कि इसका उपयोग दमन की घटनाएँ हुई। मानवाधिकारों के लिए नहीं किया जा सकता है। इंदिरा गांधी को यह कहते हैं तो इसके बाद इसका नेतृत्व नहीं करता है। इंदिरा गांधी की यह नामगवार लगा और उन्होंने केशवानन्द भारती मामले में अल्पतम हत्या के प्रयास हुए और साथ ही



में शामिल लोगों में सबसे वरिष्ठ तत्कालीन केन्द्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र की बम से हत्या कर दी गई। इन सभी बातों से पूरे देश में कानून और व्यवस्था की समस्या बढ़ने का संकेत मिलने लगा, जिसके बारे में इंदिरा गांधी के सलाहकारों ने उन्हें महीनों तक चेतावनी दी थी। इसके बाद मामले को हाथ से निकलत देख इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाने का फैसला किया। कांग्रेस पार्टी का यह फैसला देश की लोकतंत्र के लिए घाटक सिद्ध हुआ और इसे एक काला दिन के रूप में याद किया जाने लगा।

लगा।

18वीं लोकसभा के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला किया और आपातकाल की घोषणा को भारत के लोकतंत्र पर एक काला धब्बा बताया। 18वीं लोकसभा को पहले सभ्र से पहले मीडिया को संबोधित करते हुए देश के संसदीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कल 25 जून है। 25 जून को भारत के लोकतंत्र पर लगे उस कलंक के 50 साल हो रहे हैं। भारत की नई पीढ़ी की नई राजनीति संविधान में दिए गए प्रवधान के तहत समाज के गरीबों, महिलाओं, बच्चियों और दलितों की उद्यम के लिए है। जिस भारतीया पार्टी की पूरी राजनीति संविधान में दिए गए प्रवधान के तहत समाज के गरीबों, महिलाओं, बच्चियों और दलितों की उद्यम के लिए है। जिसके बाद इसके पार्टी आज संविधान की दुर्दशा करने वाली कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है।

देश के महानायक प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संविधान में कई बार इस बात का चिकित्सा किया है कि भारत की आत्मा बाबा साहब भीमराव अंवेदिकर के संविधान में बसती है और इसे संसद भी नहीं बदल सकता। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी द्वारा गलत अवधारणा फैला कर जनता को बरागालाने का काम किया जा रहा है। लोकसभा चुनावों में जनता कांग्रेस और उनके साथियों के ज्ञांसे में आ गई थी, लेकिन विपक्ष पार्टीयों की काठ की यह हांडी बार बार नहीं चढ़ी।

(लेखक मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री है)

आरपार के मूड में विपक्ष, स्पीकर ही नहीं डेप्युटी पर भी है रससाकरी

(दयाशंकर शुक्ल सागर)

हालांकि इन्हने असहज नहीं होते अगर एनडीए सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में विपक्ष के किसी सांसद को डेव्यूटी स्पीकर बनाने पर सहमति दे दी थी। 18वीं लोकसभा देश की पहली और अकेली लोकसभा थी, जिसमें कोई डेव्यूटी स्पीकर नहीं रहा। 2019 के चुनावी नीतीजों से विपक्ष इन्हने हत्या था कि भाजपा के सांसद, और विरला सांसदों के आसानी से लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए। मगर डेव्यूटी स्पीकर का पद खाली रहा।

विपक्ष के बदले तेवर: इस बार हालांकि और विपक्ष के तेवर बदले हुए हैं। उन्हें शर्त रख दी है कि अगर सरकार किसी विपक्ष नेता को डेव्यूटी स्पीकर बनाने पर विपक्ष लोकसभा स्पीकर पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। यह स्थिति सरकार के लिए एक असहज होती है।

प्रटोकॉल लिस्ट में छठा स्थान: भारत में लोकतंत्रिक संसदीय प्राप्तियां बेस्टमिस्टर रांडल पर चलती है। इस प्रणाली में लोकसभा स्पीकर को सबसे महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। सदन में स्पीकर को पार अभिनवत्व के सांसदों में उत्तरा तो यह आरपार भारत के संसदीय इतिहास में अनोखी और दुर्लभ घटना होगी। 2019 के चुनावी नीतीजों से विपक्ष नेता चुन लिए गए। मगर डेव्यूटी स्पीकर का पद खाली रहा।

विपक्ष का विश्वास अहम: स्पीकर चुनने के लिए सदन का साधारण बहुमत काफी है। इसलिए किसी सरकार को पसंद का स्पीकर चुनने में कोई



मिश्निकल नहीं होती। लेकिन संसद के सुचारू अनुच्छेद 93 कहता है कि 'लोकसभा जिती संचालन के लिए जो दो सदस्यों को स्पीकर और डेव्यूटी स्पीकर बनाने के लिए विपक्ष के लिए जिसके बाद विपक्ष को पार कर दिया गया है।' सदन में स्पीकर को पार अभिनवत्व के सांसदों में उत्तरा तो यह आरपार भारत के संसदीय इतिहास में अनोखी और दुर्लभ घटना होगी। अतीत में कई ऐसे संसदीय स्पीकरों को चुना जाए गए। विपक्ष को यह नियम अपने गठबन्धन की मजबूती को कम समझने वालों के सारे भ्रम दूर करते चलने को कृत संकल्प दिख रहा है।

कोई समर्यासीमा नहीं: संविधान का

19 जून, 2019 को गठित 18वीं लोकसभा के लिए डेव्यूटी स्पीकर का चुनाव नहीं करना 'संविधान की मूल भावना के खिलाफ' है। मगर अब 18वीं लोकसभा गठित हो चुकी है। देखा जाए तो यह पंरपरा और संविधान दोनों का अतिकरण हुआ।

संसद का सत्र: 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से सुरु हो गया। 26 जून को नए स्पीकर का चुनाव होना है। इस बार सरकार सही मायने में गठबंधन के नाजुक धारों से बंधी है। टीडीपी और जेडीयू-एन्डीए सरकार की दो बैसिक्याएं हैं। फिलहाल इनके तेवर नाम हैं लेकिन जैसी खबरें आ रही हैं कि टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू-नेता नीतीश कुमार चाहते हैं कि उनके दल का कोई संसद स्पीकर या डेव्यूटी स्पीकर चुन लेंगे।

दूध की जली बीजपी: व्यापार, गठबंधन के लिए 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार को टीडीपी का स्पीकर बनाना की परिक्रमा कर दी गई। परंपरा यह जरूर ही है कि डेव्यूटी स्पीकर का परिक्रमा हो जाए, सदन में उन्हें राजनीतिक विशेषज्ञों ने संपर्क किया जाता है। अतीत में कई ऐसे संसदीय स्पीकरों को चुना जाए गए। लेकिन बिरला इस पर सार्वजनिक टिप्पणी के लिए बड़े बदल बदलने के बारे में अपने गठबन्धन की विपक्ष को यह नहीं देखा जाता है। भाजपा भी चुप्पी साधे रहा। भाजपा भी चुप्पी साधे रहा। इसके बाद इसके लिए घाटक सिद्ध हुआ। असल समय सांसद डी पुर्देशीरी का नाम भी चाचा रहा। भाजपा भी चुप्पी साधे रहा। इसके बाद इसके लिए घाटक सिद्ध हुआ। असल समय सांसद डी पुर्देशीरी का नाम भी चाचा रहा। इसके बाद इसके लिए घाटक सिद्ध हुआ। असल समय सांसद डी पुर्देशीरी का नाम भी चाचा रहा। इसके बाद इसके लिए घाटक सिद्ध हुआ। असल समय सांसद डी पुर्देशीरी का नाम भी चाचा रहा। इसके बाद इसके लिए घाटक सिद्ध हुआ। असल समय सांसद डी पुर्देशीरी का नाम भी चाचा रहा। इसके बाद इसके लिए घाटक सिद्ध हुआ। अ

